

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

मं. 51 तर्दा दिल्ली, शनिवार, फरवरी 1, 2003 (माघ 12, 1924)  
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1, 2003 (MAGHA 12, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची

भाग I—खण्ड I—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर)	पृष्ठ	भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड—(iii) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवार नियमों, विनियमों, आदेशों तथा मंत्रक्रमों से संबंधित अधिसूचनाएं	पृष्ठ
भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवार नियमों, विनियमों, आदेशों तथा मंत्रक्रमों से संबंधित अधिसूचनाएं	.. ..	भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवार नियमों, विनियमों, आदेशों तथा मंत्रक्रमों से संबंधित अधिसूचनाएं	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, लक्षित्यों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	.. ..	भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, लक्षित्यों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मंत्रक्रमों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	1	भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मंत्रक्रमों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, लक्षित्यों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	.. ..	भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, लक्षित्यों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	पृष्ठ
भाग II—खण्ड I—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	* ..	भाग II—खण्ड I—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	पृष्ठ
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	.. ..	भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	पृष्ठ
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर र समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	.. ..	भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर र समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	पृष्ठ
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) ..	*	भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) ..	पृष्ठ
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (गंभीर आतिथ क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं ..	*	भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (गंभीर आतिथ क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं ..	पृष्ठ
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..	125	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..	पृष्ठ
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बद्ध अधिसूचनाएं और नोटिस	*	भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बद्ध अधिसूचनाएं और नोटिस	पृष्ठ
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..	पृष्ठ
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक नियामों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं ..	*	भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक नियामों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं ..	पृष्ठ
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विभाग और गैर-नोटिस	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विभाग और गैर-नोटिस	पृष्ठ
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	पृष्ठ

\*आंकड़े ग्राप्त नहीं हैं।

## CONTENTS

PAGE	PAGE		
<b>PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court</b>	<b>87</b>	<b>PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules &amp; Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)</b>	<b>131</b>
<b>PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court</b>	<b>97</b>	<b>PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence</b>	.
<b>PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence</b>	.	<b>PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.</b>	<b>131</b>
<b>PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence</b>	<b>125</b>	<b>PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs</b>	<b>389</b>
<b>PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations</b>	.	<b>PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners</b>	.
<b>PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations</b>	.	<b>PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies</b>	<b>2669</b>
<b>PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills</b>	.	<b>PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies</b>	<b>19</b>
<b>PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)</b>	.	<b>PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi</b>	.
<b>PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).</b>	.		

## भाग I—खण्ड 1

## (PART I—SECTION 1)

(गृह मंत्रालय को स्थोडकर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गई संबंधित नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएँ

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defense) and by the Supreme Court]

## गृह मंत्रालय

नई विली-110011, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

## संकल्प

सं 25011/41/2001-जी०पी०ए०-॥/पी०ए०-॥—  
भारत सरकार ने दिनांक 28 अगस्त, 1970 के संकल्प संख्या ४/136/६८-पी० । (कार्मिक ।) के द्वारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का गठन किया है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के विभिन्न प्रभागों के कार्य दिनांक 13 सितम्बर, 1973 के संकल्प सं 34/1/73 बी०पी०आर०ए० डी०/जी० पी० ए०-। के द्वारा पुनरीक्षित किए गए थे।

2. देश में उपलब्ध राज्य विधि विज्ञान सेवाओं का स्तर और इसके विकास में बाधक त्रुटियों एवं कठिनाईयों की जांच विभिन्न समितियों द्वारा समय-समय पर की गई थी। यह सिफारिश की गई कि देश में आपराधिक न्याय प्रदान करने वाली प्रणाली में सुधार के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की चाहुंसूची दर्शता और कार्यकरण को उन्नत बनाने की आवश्यकता है। यह सिफारिश भी की गई थी कि राष्ट्रीय स्तर पर विधि विज्ञान कार्यकलापों के निरन्तर उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए मृह मंत्रालय के अन्तर्गत एक ही छत्र के नीचे सभी केन्द्रीय विधि विज्ञान संस्थानों को समेकित किया जाना चाहिए।

3. सभी सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त, सरकार ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय के संघे ब्रभार के अधीन विधि विज्ञान का एक अलग निदेशालय, नई दिल्ली में स्थापित करने का निर्णय लिया है। कोलकाता, चट्ठोबढ़ी और हैदराबाद स्थित केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएँ और कोलकाता, शिमला और हैदराबाद स्थित प्रश्नालयक दस्तखेजों के सरकारी निरीक्षक की विधि विज्ञान, निदेशालय के अन्तर्गत रखा जायेगा। निदेशालय का अध्यक्ष एक विधि वैज्ञानिक होगा जिसे निदेशक-सह-मुख्य विधि वैज्ञानिक के रूप में पदनामित किया जायेगा।

4. मृह मंत्रालय के दिनांक 13 सितम्बर, 1973 के पहले के संकल्प सं 34/1/73-बी०पी०आर० ए० डी०/जी०पी०ए०-। में वर्णित कर्तव्यों के धोषणा-पत्र का अतिक्रमण करते हुए, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो तथा विधि विज्ञान निदेशालय के कर्तव्यों का धोषणा-पत्र अनुलग्नक I और II में दिए गए अनुसार होगा।

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, महानिदेशक; पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो; निदेशक-सह-मुख्य विधि वैज्ञानिक; विधि विज्ञान निदेशालय; निदेशक, आसूचना ब्यूरो; निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो; महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल; महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस; महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल; निदेशक, समन्वय एवं पुलिस बेतार; निदेशक, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी; निदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड; निदेशक, विशेष सुरक्षा ब्यूरो; निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भिजवाई जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ती० गोपाला स्वामी, सचिव

## अनुलग्नक-

विधि विज्ञान निदेशालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कर्तव्यों का नया धोषणा-पत्र

- \* न्याय प्रदान करने वाली प्रणाली की वैज्ञानिक रूप से मदद करना।
- \* अपने प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से न्यायपालिका और अन्य जांचकर्ताओं को विधि ज्ञान और विशेषज्ञता का प्रचार करना और परामर्शी तथा मन्त्रणा सेवाएं प्रदान करना।
- \* देश में विधि विज्ञान एवं संबंधित सेवाओं की समस्याओं को पहचान करना एवं केन्द्र सरकार के स्तर पर सभी विधि विज्ञान गतिविधियों को आरम्भ करना, उन्हें बढ़ावा देना, मार्गदर्शन प्रदान करना, उन्हें प्रोन्तु करना और उन पर नियन्त्रण करना।
- \* देश में आपराधिक न्याय प्रदान करने वाली प्रणाली में वैज्ञानिक सहायता को बढ़ाने के लिए भारत एवं विदेशों में स्थित संस्थानों, संगठनों, मन्त्रालयों, विश्वविद्यालयों,

- \* पुलिस, अधियोजकों और अन्य विधि प्रवर्तन तथा नियामक ऐजेंसियों के साथ प्रभावी सम्बन्ध स्थापित करना।
- \* आपराधिक व्याय प्रदान करने वाली प्रणाली में विधि प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण के लिए गृह मन्त्रालय, भारत सरकार को तकनीकी सलाह एवं सेवाएं प्रदान करना।
- \* राष्ट्रीय स्तर पर विधि विज्ञान गुणता आस्तासन और प्रत्यायन कार्यक्रम का समयबद्ध कार्यविधयन का समन्वय करना और देश में विधि विज्ञान सेवाओं के लिए प्रबोधनता जांच आयोजित करने के लिए एक नोडल ऐजेंसी के तौर पर भी कार्य करना। निजी विधि प्रैक्टीशनरों के प्रत्यायन को बढ़ावा देना और विधि विज्ञान प्रक्रिया में “नैतिकता” को शामिल करना।
- \* सरकार द्वारा समय-समय पर सन्दर्भित की गई विधि विज्ञान प्रक्रियाओं, संहिताओं, चालू प्रक्रियाओं, विधिक ढांचे और अन्य सम्बन्धित मामलों का मूल्यांकन एवं पुनरीक्षण करना।
- \* विधि प्रवर्तन ऐजेंसियों और न्यायपालिका की सहायता हेतु विधि विज्ञान प्रक्रिया के विकासशील और नए क्षेत्रों के मूल्यांकन के लिए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय और तकनीकी, दोनों प्रकार से मार्ग दर्शन और सहायता प्रदान करना।
- \* समूचे देश से और संसार से प्राप्त वैज्ञानिक डाटावेस और अन्य जानकारी का रख-रखाव और विधि विज्ञान सूचना सम्पर्क स्थापित करते हुए विधि विज्ञान संस्थानों के लिए गाहु बनाना।
- \* राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास कार्यक्रम को विधि विज्ञान में शामिल करना और इसके कार्यविधयन को मानीटर करना। विधि वैज्ञानिकों (केन्द्र के साथ राज्यों के भी) को भारत और विदेशों की आधुनिकतम वैज्ञानिक तकनीकों में विशेषज्ञता प्राप्त विकसित प्रशिक्षण का समन्वय करना।
- \* देश के विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में विधि विज्ञान शिक्षण और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- \* अपराध जांच में वैज्ञानिक तरीकों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित करना।
- \* कोलकाता, चण्डीगढ़ और हैदराबाद/शिमला में स्थित केन्द्रीय विधि विज्ञान संस्थानों (केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं और प्रश्नात्मक दस्तावेजों के सरकारी निरीक्षकों) की प्रशासनिक और संचालनात्मक गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना।
- \* विधि विज्ञान निदेशालय के अंतर्गत केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं/प्रश्नात्मक दस्तावेजों के सरकारी निरीक्षकों में विधि विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना और उसे हाथ में लेना।
- \* विधि विज्ञान निदेशालय के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं/प्रश्नात्मक दस्तावेजों के सरकारी निरीक्षकों को आधुनिकतम वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा अपराध मामलों की जांच कार्य करने योग्य बनाने के लिए समुचित मूलभूत सुविधाओं और मानव संसाधनों का विकास करना।
- \* विधि विज्ञान पर सेमिनार, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित करना।
- \* विधि विज्ञान निदेशालय के अंतर्गत कनिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप योजना की द्रगति को मानीटर करना और पुरस्कृत करना।

## अनुलग्नक- ॥

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के कार्य

1. अनुसंधान सांस्कृतिकों और प्रकाशन प्रभाग

पुलिस को प्रभावित करने वाले अपराध और सामान्य प्रकृति की समस्याओं का विश्लेषण और अध्ययन करना; जैसे कि

- a) अपराध की प्रवृत्ति और कारण;
- b) अपराध की रोकथाम रोकने के तरीके, उनकी कारगरता और अपराध के साथ उनका संबंध;
- c) पुलिस बलों का प्रबन्ध, संख्या, प्रशासन, तरीके, प्रक्रियाएं और तकनीकों और उनका आधुनिकीकरण, पुलिस अधिनियम और मैनुअल;
- d) जांच के तरीकों को बेहतर बनाना और वैज्ञानिक सहायता साधा और सजा शामिल करने को उपयोगिता और उसके परिणाम;
- e) कानूनों की अपर्याप्तता;
- f) वाल अपराध;
- g) पुलिस वर्दी, वैच, पदक, उपाधिशां, कलर और झंडे, पुलिस ड्रिन, प्रक्रिया वारंट इत्यादि।

2. राज्यों में पुलिस अनुसंधान कार्यक्रमों की सहायता, अनुसंधान परियोजनाओं को प्रक्रिया और समन्वय; अन्तर्मिति अनुसंधान कार्य को प्रयोजित करना;
3. पुलिस अनुसंधान संबंधी स्थायी समिति से संबंधित कार्य;
4. पुलिस समस्याओं के अध्ययन से संबंधित पुलिस विज्ञान कांसेस और अन्य सम्मेलन और सेमिनार;
5. सामाजिक सुरक्षा और अपराध रोकथाम कार्यक्रमों में भागीदारी;

6. अपराध की रोकथाम और अपराधियों के उपचार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के कार्य में भागीदारी;
7. अपराध की अखिल भारतीय सांहिकीय कारखन-रखाव;
8. अपराध की प्रवृत्तियों का सांहिकीय विश्लेषण;
9. पुलिस विज्ञान और अपराध विज्ञान से संबंधित प्रलेखन;
10. निम्नलिखित का प्रकाशन :—

- i) पुलिस अनुसंधान और विकास पत्रिका;
- ii) भारत में अपराध;
- iii) भारतीय पुलिस पत्रिका (Journal)
- iv) दुर्घटनामक मौतें और आत्महत्याएं;
- v) अनुसंधान रिपोर्टें और समाचार पत्र;
- vi) पुलिस कार्य से संबंधित मामलों के संबंध में रिपोर्टें, समीक्षाएं, अन्य पत्रिकाएं और पुस्तकें।

## II. विकास प्रभाग

1. भारत में पुलिस बलों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों के कार्य की समीक्षा और निम्नलिखित क्षेत्रों में नए उपकरणों का विकास :—
  - क) शस्त्र और गोला-बारूद;
  - ख) दंगा नियंत्रण उपकरण;
  - ग) यातायात नियंत्रण उपकरण;
  - घ) पुलिस परिवहन; और
  - ड) जांच के लिए विविध वैज्ञानिक उपकरण और वैज्ञानिक सहायक उपकरण।
2. उपरोक्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों और संस्थानों और सरकारी और निजी उपकरणों के साथ सम्पर्क, विकास कार्यक्रमों का समन्वय और पुलिस उपकरण के देशी उत्पादन को प्रेरित करना।
3. पुलिस कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटर तकनीक का प्रयोग करना।
4. पुलिस प्रचार और पुलिस प्रचार फाईलें, पुलिस संस्थान और परेड़े।
5. पुलिस अनुसंधान और पुलिस अनुसंधान के अलावा विकास सलाहकार परिषद और इसकी स्थाई समितियों से संबंधित कार्य।

## III. प्रशिक्षण प्रभाग

1. बदलती सामाजिक परिस्थितियों में पुलिस प्रशिक्षण और इस क्षेत्र में देश की आवश्यकताओं के लिए किए गए प्रबंध की समय-समय पर समीक्षा करना और प्रशिक्षण और पुलिस कार्य में वैज्ञानिक तकनीकों को शामिल करना और पुलिस प्रशासन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में

- प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को बनाना और उनका समन्वय करना।
- केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कोलकाता, हैदराबाद और चण्डीगढ़।
- राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विभिन्न रैंकों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य विवरण और पाठ्यचर्चा रहित, प्रशिक्षण प्रबंधों में मानकीकरण एवं एकलृपता, जैसाकि वांछनीय है सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना और नई चुनौतियों और समस्याओं से निपटने के लिए समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों और सुधारों के सम्बन्ध में सलाह देना।
- विभिन्न ग्रेडों और पुलिस प्रस्तावों की किस्मों के लिए जल्दी समझे जाने वाले नए पुनर्शवर्या, प्रोन्नति, विशेषज्ञता और ऑरिएन्टेशन पाठ्यक्रम बनाने में सहायता करना।
- केन्द्रीय चिकित्सा विधिक संस्थान और केन्द्रीय यातायात संस्थान की स्थापना के सम्बन्ध में कार्य।
- इन संस्थानों में प्रयोग के लिए पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के समन्वय से मानक मैनुअल, पाठ्य पुस्तकें, पैमफलेट व्याख्यान, टिप्पणियां, नमूना अध्ययन, व्यवहारिक अभ्यास एवं अन्य शैक्षणिक साहित्य तैयार करना।
- राज्यों के महानिरोक्षकों/उप महानिरोक्षकों (परिक्षण) को सम्बद्ध साहित्य अधिकारियों को परिचालित करने के लिए बांटना, ताकि उन्हें प्रशिक्षण संकल्पना से अवगत कराया जा सके और उच्च रैंकों में प्रशिक्षण चेतना को बढ़ाया जा सके।
- प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सहायक उपकरणों के लिए उपकरणों का मानकीकरण और उनके उत्पादन और विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों को आपूर्ति करने के लिए प्रबंध करना।
- विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रयोग के लिए फिल्मों का एक चल संग्रहालय बनाना और उसका रख-रखाव करना।
- देश के अन्दर और बाहर के उपयुक्त गैर-पुलिस संस्थानों में विभिन्न रैंकों के पुलिस अधिकारियों प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करना।
- पुलिस प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के अध्यक्षों की वार्षिक संशोधनी और छोटे समिनारों का आयोजन करना।
- समय-समय पर यथा-आवश्यक केंद्र के तहत नए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का सुझाव देना।
- भारत और विदेश से पुलिस कार्य के विभिन्न पहलुओं पर पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण के तरीकों, पढ़ाने के सहायक उपकरणों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और साहित्य से संबंधित

सूचना के लिए एक विवरण केन्द्र के रूप में कार्य करना।

14. केन्द्रीय और राज्य बुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में पुस्तकालयों के विकास में सहायता प्रदान करना।
15. यू० एन० डी० पी० यूनेस्को और कोलम्बो यौजना इत्यादि के तहत अन्य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षण सहायक उपकरण परियोजनाओं और फैलोशिप के संबंध में कार्मिक विभाग के प्रशिक्षण निदेशालय के साथ सम्पर्क बनाना।

#### IV. सुधारात्मक प्रशासन

1. जेल सांचियों और जेल प्रशासन को प्रभावित करने वाली सामान्य प्रड़ति की समस्याओं का विश्लेषण और अध्ययन करना।
2. सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में राज्यों को संगत सूचना का आत्मसात करना और उसका प्रचार करना।
3. सुधारात्मक प्रशासन में आर०आई०सी०ए० एवं अन्य शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों द्वारा आयोजित किए गए अनुसंधान अध्ययनों का समन्वय करना और राज्य सरकारों के परामर्श से अनुसंधान अध्ययनों/सर्वेक्षणों के आयोजन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना।
4. बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों को महेनजर रखते हुए, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समीक्षा करना, नई

वैज्ञानिक तकनीकों और अन्य संबंधित पहलुओं को शामिल करना।

5. सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में जेल स्टाफ को विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण देने के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य विवरण और पाठ्यचर्चा इत्यादि सहित एकरूप प्रशिक्षण मोड्यूल तैयार करना।
6. सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में रिपोर्टों, न्यूज लैटरों, बुलेटिनों को प्रकाशित करना और दृश्य-अव्य सहायक उपकरणों इत्यादि को तैयार करना।
7. सुधारात्मक प्रशासन से सम्बन्धित कार्य के मार्गदर्शन के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करना।

#### राजधानी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 2003

#### संकल्प

सं. 1/20017/02/99-रा०भा० (नीति-1) :—दिनांक 19 जून, 2000 को भारत सरकार के समसंबंधक संकल्प द्वारा पुर्णगठित केन्द्रीय हिन्दी समिति में डॉ० बाई० लक्ष्मी प्रसाद, को गैर सरकारी सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाता है।

हम०एल० मुप्ता, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110011, the 31st December 2002

#### RESOLUTION

No. 25011/41/2001-GPA.II/PM.II.—The Government of India have set up Bureau of Police Research & Development vide the resolution No. 8/136/68-P.I (Pers. I) dated 28th August, 1970. The functions of the different divisons of BPR&D were revised by the Resolution No. 34/1/73-BPR&D/GPA.I dated 13th September, 1973.

2. The status of State Forensic Science Services available in the country and the inadequacies and impediments that had obstructed its development were examined by various committees from time to time. It was recommended that there was need to upgrade the all-round competency and functioning of the Forensic Science Laboratories to improve the criminal justice delivery system in the country. It was also recommended that to ensure constant upgradation of Forensic Science activities at the national level there should be integration of all the Central Forensic Science Institutions under one umbrella under the Ministry of Home Affairs.

3. After carefully considering all the recommendations, Government have decided to create a separate Directorate of Forensic Science in New Delhi under the direct charge of the Ministry of Home Affairs, Government of India. The Central Forensic Science Laboratories at Kolkata, Chandigarh and Hyderabad and Government Examiner of Questioned Documents at Kolkata, Shimla and Hyderabad will be placed under the Directorate of Forensic Science. The Directorate will be headed by a Forensic Scientist who will be designated as Director-cum-Chief Forensic Scientist.

4. The Charter of Duties of Bureau of Police Research & Development and the Directorate of Forensic Science will be

as laid down in the Annexures I & II in supersession of the charter of duties mentioned in the annexure to the Ministry of Home Affairs earlier Resolution No. 34/1/73-BPR&D GPA-I dated 13 September, 1973.

#### ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments/Union Territory Administrations; Director General, Bureau of Police Research & Development; Director-cum-Chief Forensic Scientists; Directorate of Forensic Science; Director, Intelligence Bureau; Director, Central Bureau of Investigation; Director General, Border Security Force; Director General, Indo-Tibet Border Police; Director General, Central Industrial Security Force, Director of Coordination and Police Wireless; Director, SVP National Police Academy; Director, National Institute of Criminology and Forensic Science, Director, National Security Guard; Director, Special Security Bureau; Director, National Crime Records Bureau and All Ministries/Departments of Governments of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. GOPALASWAMI  
Secy.

#### Annexure-I

#### NEW CHARTER OF DUTIES OF DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE, MINISTRY OF HOME AFFAIRS,

To scientifically assist the justice delivery system.

To disseminate the forensic knowledge and expertise with and render advisory & consultancy services to judiciary & other investigators through their training institutions.

: Identify the problems of the forensic science and allied services in the country and initiate, stimulate, guide, promote and control all the forensic science activities at Central Government level.

Establish effective linkages with institutions, organisations, ministries, universities, police, prosecutors and other law enforcement and regulatory agencies in India and abroad for promotion of scientific aids in the criminal justice delivery system in the country.

Render technical advice and services to the Ministry of Home Affairs, Govt. of India for modernisation of forensic practices in Criminal Justice Delivery System.

Coordinate for time bound implementation of forensic science quality assurance and accreditation programme at national level and also act as nodal agency for conduct of proficiency testing for forensic science service in the country. Encourage accreditation of private forensic practitioners and evolve ethics in forensic science practice.

Assess and review the forensic science procedures, manuals, current practices, legal framework and other related matters, as may be referred by the Government from time to time.

Guide and assist State FSLs, Universities and other Academic Institutions both, financially and technically to assess, evaluate and develop emerging and new areas of forensic science, practice to help the law enforcement agencies and judiciary.

Maintain scientific database and other information from across the country and the world, and make it accessible to forensic science institutions by establishing forensic science information highways.

Evolve human resource development programme in forensic science at national level and monitor its implementation. Coordinate specialised advanced training to the forensic scientists (Central and as well as State) in the latest scientific techniques in India and abroad.

- \* Promote forensic science teaching and research & development activities in universities and other institutions in the country.
- \* Liaise with other govt. and non-government organisations for generation of public awareness on scientific aids in crime investigation.
- \* Control the administrative and operational activities of the Central Forensic Science Institutes (CFSIs & GEQD) at Kolkata, Chandigarh and Hyderabad/Shimla.
- \* Promote and undertake research work in the area of Forensic Science in the CFSIs/GEsQD under the Directorate of Forensic Science.
- \* Develop appropriate infrastructural facilities and human resources in the CFSIs/GEsQD under Directorate of Forensic Science to enable them to undertake examination of crime case exhibits employing latest scientific techniques.
- \* Organise Seminars, workshops and Symposia on Forensic Science.
- \* Award and monitor progress of the Junior Research Fellowship Scheme under Directorate of Forensic Science.

#### Annexure-II

#### FUNCTIONS OF BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT

##### I. RESEARCH STATISTICS AND PUBLICATION DIVISION

Analysis and study of crime and problems of general nature affecting the police, e.g.,

- (a) Trends and causes of crime;

- (b) Prevention of crime—Preventive measures, their effectiveness and relationship with crime;
- (c) Organization, strength, administration, methods, procedures and techniques of the police forces and their modernisation; police act and manuals;
- (d) Improvements in methods of investigation, utility and results of introducing scientific aids and punishment;
- (e) Inadequacy of laws;
- (f) Juvenile delinquency;
- (g) Police Uniform, badges, medals, decorations, colours and flags, police drill, warrant of procedure etc.

2. Assistance of Police Research programmes in States, processing and coordination of research projects; sponsoring extra-mural research.

3. Work relating to Standing Committee on Police Research.

4. Police Science Congress & other conferences and seminars relating to study of police problems.

5. Participation in social defence and crime prevention programmes.

6. Participation in work of the United Nations in the field of prevention of crime and treatment of offenders,

7. Maintenance of all India statistics of crime.

8. Statistical analysis of trends of crime.

9. Documentation relating to Police Science and Criminology.

10. Publication of :

- (i) Police Research & Development Journal
- (ii) Crime in India
- (iii) Indian Police Journal
- (iv) Accidental Deaths and Suicides
- (v) Research Reports and News letters
- (vi) Reports, Reviews, other journals and books relating to matters connected with police work.

#### II. DEVELOPMENT DIVISION

1. Review of the performance of various types of equipment used by the police forces in India and development of new equipment in the following fields :

- (a) Arms and Ammunition;
- (b) Riot Control Equipment;
- (c) Traffic Control Equipment;
- (d) Police Transport; and
- (e) Miscellaneous scientific equipment and scientific aids to investigation.

2. Liaison with the National laboratories, various scientific organisations and institutions and public and private sector undertakings in the above fields; coordination of development programmes and stimulating indigenous production of police equipment.

3. Application of computer technology in various fields of police work.

4. Police publicity and police publicity files, police weeks and parades.

5. Work relating to Police Research & Development Advisory Council and its Standing Committees, other than on police research.

### III. TRAINING DIVISION

1. To review from time to time the arrangements for Police training and the needs of the country in this field in the changing social conditions and the introduction of scientific techniques in training and in police work and to formulate and coordinate training policies and programmes in the field of police administration and management.
2. Central Detective Training Schools, Calcutta, Hyderabad & Chandigarh.
3. To evaluate training programmes with a view to securing such standardisation and uniformity in the training arrangements including courses, syllabi and curricula for various ranks in the States/Union Territories as may be desirable and to suggest modifications and improvements that may be considered necessary from time to time to meet new challenges and problems.
4. To help devise new refresher, promotion, specialist and orientation courses considered necessary for the different grades and kinds of police officers.
5. Work relating to the establishment of the Central Medico Legal Institute and the Central Traffic Institute.
6. To prepare, in coordination with the police training institutions, standard manuals, textbooks, pamphlets, lecture notes, case studies, practical exercises and other educative literature for use in these institutions.
7. To distribute relevant literature to Inspectors General/DIsG (Training) in the States for circulation to officers in order to familiarise them with training concepts and to strengthen training consciousness among the higher ranks.
8. To standardise equipment for training and training aids and to arrange for their production and supply to the various training institutions.
9. To create and maintain a circulating library of films for the use of various police training institutions.
10. To assist in the training of police officers of police various ranks at appropriate non-police institutions inside and outside the country.
11. To organise the annual Symposium of the Heads of Police Training Institutions and short Seminars on various aspects of Police training.
12. To suggest the establishment of new training institutions under the Centre as necessary from time to time.
13. To act as a clearing house for information relating to Syllabi, methods of training, teaching aids, training programmes and literature on various aspects of police work etc from India and abroad.
14. To help in the development of libraries in the Central and State Police training institutions.
15. To liaise with the Directorate of Training of the Department of Personnel in relation inter-alia to training aids projects and, fellowships under the UNDP, UNESCO & Colombo Plan etc.

### IV. CORRECTIONAL ADMINISTRATION

1. Analysis and study of prison statistics and problems of general nature affecting Prison Administration.
2. Assimilation and dissemination of relevant information to the States in the field of Correctional Administration.
3. Coordination of Research Studies conducted by RICAs and other Academic/Research Institutes in Correctional Administration and to frame guidelines for conduct of research studies/surveys in consultation with State Governments.
4. To review training programmes keeping in view the changing social conditions, introduction of new scientific techniques and other related aspects.
5. To prepare uniform Training Module including course, syllabi, curriculum, etc. For providing training at various levels to the Prison staff in the field of Correctional Administration.
6. Publication of reports, newsletters, bulletins and preparation of Audio Visual aids etc. in the field of Correctional Administration.
7. To set up an Advisory Committee to guide the work relating to Correctional administration.

### DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi, the 21st January 2003

#### RESOLUTION

No. I/20017/02/99-O.L. (Policy-1).—Dr. Y. Laxmi Prasad, is co-opted as non-official member in the Kendriya Hindi Samiti, reconstituted by Government of India vide Resolution of even No. dated 19-06-2000.

M. L. GUPTA  
Joint Secretary